

व्यवस्था सम्मिलित है —

(₹० लाखों में)

1. कृषि और अन्य सम्बद्ध कार्यक्रम	2435
2. महकारिगता एव मामुदायिक विकाम	145
3. मिचाई व बिजली	819
4. उद्योग व खनन	162
5. पत्रिवहन एव सचार	1455
6. समाज सेवाए	148५
7. विविध	6
कुल	6505

उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास के लिए
केन्द्रीय सहायता

1026. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) तीन योजनाओ, तीन वार्षिक योजनाओ तथा चौथी पञ्चवर्षीय योजना मे उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना महायता अनुदान दिया गया था ,

(ख) क्या पहले दी जा रही 24 करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता अत्र बन्द कर दी गई है और यदि हा, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या उत्तराखण्ड मे अन्यधिक निर्धनता को दृष्टि मे रखते हुए सरकार का विचार इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बढ़ा हुआ केन्द्रीय सहायता अनुदान पुन आरम्भ करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम धारिया) (क) उत्तराखण्ड मे उत्तर काशी, चमोली और पिथौरागढ जिले शामिल है, उत्तराखण्ड के त्वरित विकास की स्कीम को वर्ष 1960 मे अन्तिम रूप दिया गया। तब से भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय महायता दी जा रही है। उत्तराखण्ड की विवाप योजना के लिए अनुदान के रूप मे दी गयी केन्द्रीय महायता इस प्रकार है

अनुदान करोड रुपये में

1960-61	0 50
तीसरी पञ्चवर्षीय योजना	11 62
तीन वार्षिक योजनाये—	
1966-67	1 90
1967-68	1 97
1968-69	1 65

राज्य की चौथी योजना मे उत्तराखण्ड के लिए 20 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमे से आधा अनुदान होगा। चौथी योजना के आरम्भ के तीन वर्षों मे राज्य की वार्षिक योजनाओ मे उत्तराखण्ड मे लिए निम्नलिखित परिव्यय शामिल किये गये है

करोड रुपये

1969-70	3 50
1970-71	4 36
1971-72	4 00

(ख) जी, नहीं। तीसरी योजना मे केन्द्रीय सहायता का आवकन 24 करोड रुपये था, जिसमे

से राज्य सरकार को वास्तविक व्यय के आघार पर 18.58 करोड़ रुपये अदा किये गये थे। जैसा पहले ही कहा जा चुका है उत्तर प्रदेश की चौथी योजना में उत्तराखण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये का परिबन्ध रखा गया है इसके लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्रीय सहायता द्वारा की जायेगी।

(ग) क्योंकि उत्तराखण्ड की विकास योजना के लिए अनुदान और ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता जारी है अतः उसे पुनः आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता। यदि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये में अधिक की व्यवस्था करना सम्भव हो सके तो सहायता-अनुदान की गति तदनु रूप बढ़ जायेगी।

**Fake Exchange Permit Racket Uncarthed
by Reserve Bank of India**

1027. SHRI N. K. SANGHI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether an exchange permit racket of drawing foreign exchange by means of faked exchange permits, has come to the notice of the Reserve Bank of India and that the Enforcement Directorate is vigorously investigating into the matter.

(b) if so, the result thereof, and the amount of foreign exchange involved ; and

(c) whether any particular bank is involved in this ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (c). It is reported by the Reserve Bank of India that they have come across an instance of drawal of foreign exchange of U.S Dollars 1,850, each through two different banks on permits bearing the same number. It is suspected that one of these drawals may be against a fake exchange permit and the matter is under scrutiny.

No such case is under investigation by the Directorate of Enforcement

**Ownership Pattern of Companies
Publishing Newspapers**

1028. SHRI JYOTIRMOY BOSU :
SHRI MAYAVAN :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government have prepared a study of the ownership pattern of the Companies publishing newspapers ; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) and (b). A departmental study of the ownership pattern of the companies publishing newspapers has been instituted by the Department of Company Affairs.

In the annual publication "The Press in India", the Registrar of Newspapers in India publishes some data on the ownership of newspapers. These data are based on the annual statements furnished by the newspapers to the Registrar of Newspapers in accordance with the Press and Registration of Books Act.

**Aid for Development of Backward
Areas of U.P.**

1029 SHRI S. M. BANERJEE : Will the MINISTER OF PLANNING be pleased to state :

(a) the financial aid likely to be given to Uttar Pradesh during the Fourth Plan for developing the backward areas ;

(b) whether any request has been made by the Chief Minister of Uttar Pradesh to the Union Government in this regard ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI